



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2019/पोष 2, 1941

No. 395]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2019/PAUSA 2, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2019

मामला सं. एसएसआर 14/2019

विषय - चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से "फ्लैक्स फैब्रिक्स" के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात वूवन फैब्रिक्स (50 प्रतिशत से अधिक फ्लैक्स मात्रा वाले) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।

फा. सं. 7/26/2019-डीजीटीआर 1.—जबकि वर्ष 1995 में और उसके बाद यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और हांगकांग (जिन्हें यहां आगे सामूहिक रूप से संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लैक्स फैब्रिक्स" के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात वूवन फैब्रिक्स (50 प्रतिशत से अधिक फ्लैक्स मात्रा वाले) (जिसे आगे संबद्ध सामान कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की।

1. आवेदक ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग के लिए सामग्री की चोट विषय देश से डंप किए गए आयात के कारण हो रही है और इस विषय से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। देश।

प्रष्ठभूमि

2. याचिकाकर्ता चीन जन. गण. और हांगकांग से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में मूल जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं. 14/8/2008-डी जी ए डी द्वारा शुरू की गई थी। चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा 17/02/2009 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे। और जबकि अनंतिम शुल्क दिनांक 26 मार्च, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 30/2009-सीमाशुल्क द्वारा लगाए गए थे। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए 1 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/08/2008-डी जी ए डी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए। संबद्ध सामानों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 21 दिसंबर, 2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 142/2009-सीमाशुल्क द्वारा लगाया गया था।
3. प्राधिकारी ने दिनांक 10 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. 15/30/2013-डीजीएडी द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और जांच पूरी की। उसके बाद प्राधिकारी ने चीन जन. गण. तथा हांगकांग से फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों पर दिनांक 9 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 15/30/2013-डीजीएडी द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया। ये 12 अगस्त, 2015 की अधिसूचना सं. 39/2015-सीमाशुल्क द्वारा लगाये गए थे।

समान वस्तु

4. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं तकनीकी विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। ग्राहक इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।

घरेलू उद्योग

5. यह आवेदन पत्र मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. – जया श्री टेक्सटाइल्स द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही संबद्ध देश में किसी संबद्ध सामानों के निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध है।
6. इस याचिका का समर्थन मै. रेमेंड तथा मै. बॉम्बे रेयन द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 18 लघु उत्पादकों ने भी समर्थन पत्र दायर किए हैं :
 - i. मै. बी.के. टेक्सटाइल्स
 - ii. मै. बालेश्वर स्यानफैब एलएलपी
 - iii. मै. केशरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - iv. मै. सिल्वरलाइन फैशन फैब्रिक्स लि.
 - v. मै. विराट फैशन वीविंग ट्रेन्ड्स
 - vi. मै. त्रिजेश नेचुरल फाइबर एंड फैब्रिक्स (इंडिया) प्रा. लि.
 - vii. मै. भावना फैब्रिक्स
 - viii. मै. आरएसएल डाईकोट प्रा. लि.

- ix. मै. कोटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
- x. मै. जगदम्बा टैक्सटाइल्स प्रा. लि.
- xi. मै. स्वाति विनायक सिंथेटिक्स लि.
- xii. मै. राघव इंटरप्राइजेज
- xiii. सी एंड आर टैक्सटाइल्स प्रा. लि.
- xiv. मै. वेब्स मधुसूदन
- xv. मै. मिनेश आर पारेख
- xvi. मै. धर्शन क्रिएशन प्रा. लि.
- xvii. मै. ली वीविंग
- xviii. मै. वरनी वैलवेब्स

7. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि नियमों के नियम 2 (बी) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में 'घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा की ओर से' आवेदन किया गया है।

पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

8. सामान्य मूल्य: आवेदकों ने दावा किया है कि चीन के मामले में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसरण में निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक का दावा है कि फ्रांस को एक "सुरोकेट" देश के रूप में विचार किया जाना चाहिए और उचित समायोजन के पश्चात यूरोपीय संघ के भाग का गठन करने वाले अन्य देशों ने फ्रांस से निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
9. हांगकांग के मामले में, आवेदकों ने उचित समायोजन के पश्चात, हांगकांग में आने वाले उत्पादों की आयात कीमत पर विचार करते हुए, हांगकांग में उपभोग कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
10. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ भली भांति समायोजित, उत्पादन की लागत के आधार पर और विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों के लिए परिवर्धनों के पश्चात, सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
11. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। कीमत समायोजन को समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, व्ययों, पत्तन व्ययों, बैंक प्रभारों और समुद्री बीमा और चीन के मामले में वैट अंतरों के कारण अनुमति दी गई है।
12. सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के अनुमानों पर विचार करते हुए, प्रत्येक संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। परिणामी पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण हैं और न्यूनतम सीमाओं से बहुत अधिक हैं। इस बात के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक हैं जो प्रथम दृष्टया संकेत करते हैं कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर निर्यातित होना जारी हैं जो इस प्रकार लगातार पाटन को दर्शाता है और जांच की शुरुआत किए जाने का औचित्य सिद्ध करता है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

14. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग पर मात्रा प्रभाव के कारण डंपिंग और परिणामी चोट के प्राइमरी साक्ष्य हैं। उत्पादन में कमी, बिक्री और क्षमता उपयोग और मूल्य प्रभाव में कटौती के कारण मूल्य और बिक्री के तहत मूल्य में कमी के कारण लाभ कम हो जाता है। कैपिटल एम्प्लॉइड (आरओसीई) और कैश फ्लो पर। इसके अलावा, इस विषय में उत्पादकों / निर्यातकों की क्षमता और निर्यात अभिविन्यास के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए डेटा भी प्रथम दृष्टया एडी ड्यूटी के समापन पर डंपिंग और परिणामी चोट की संभावना को इंगित करते हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

15. और दायर विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

विचाराधीन उत्पाद

16. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्स फैब्रिक है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच के अनुसार उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था :

“विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल का अथवा वहां से निर्यातित वूवन फैब्रिक्स है जो सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय-53 के तहत सामान्य रूप से वर्गीकृत है। “फ्लैक्स” और “लिनेन” पर्यायवाची हैं और फ्लैक्स शब्द लिनेन के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रयोग प्रायः ओवन बैड, बाथ टब, टेबिल और किचन टेक्सटाइल की श्रेणी वर्णित करने के लिए जेनेरिक संदर्भ में किया जा सकता है क्योंकि पारंपरिक रूप से फ्लैक्स का व्यापक रूप से प्रयोग तौलिया, शीटों आदि के लिए किया जाता था। उत्पाद को उप शीर्ष 53.09 पर सीमाप्रशुल्क अध्याय-53 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वूवन फैब्रिक 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैक्स मात्रा और संबद्ध देशों से आयातित किया जा रहा वूवन फैब्रिक समान वस्तुएं हैं और नियमावली के अभिप्राय से विचाराधीन उत्पाद हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रेड-वार उत्पादन विवरण के अनुसार, घरेलू उद्योग 30-50% के फ्लैक्स मात्रा वाले कपड़े का उत्पादन करता है। यह कुल उत्पादन का 0.62% है। चूंकि, घरेलू उद्योग 50%, तक के फ्लैक्स मात्रा वाले कपड़े का उल्लेखनीय उत्पादन नहीं कर रहा है, इसलिए प्राधिकारी ने 50% से अधिक फ्लैक्स मात्रा वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्णय किया है।”

17. संबद्ध सामान उपशीर्ष 5309 के तहत सीमाप्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि संबद्ध सामान उप शीर्ष 5309 के तहत आयातित किए जा रहे हैं। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

संबद्ध देश

18. यह जांच एक निर्णायक समीक्षा है अतः मूल जांच में संबद्ध देशों का क्षेत्र संबद्ध देशों तक सीमित है अर्थात् चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के विरुद्ध है।

जांच की अवधि

19. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2018 से जून, 2019 (15 माह) होगी और क्षति जांच अवधि अप्रैल 2015 से मार्च 2016, अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तथा अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 और तथा जांच की अवधि होगी।

प्रक्रिया

20. इस समीक्षा जांच में चीन जन.गण. और हांगकांग से फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 9 जून, 2015 की अधिसूचना सं 15/30/2013-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे।
21. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

22. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों और संबद्ध वस्तुओं से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है।
23. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से जांच से संबंधित अपने अनुरोध भी कर सकते हैं। यह सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जा सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी**व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****भारत सरकार****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,****नई दिल्ली- 110001**

24. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर प्राधिकरण तक पहुंच सके। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त नियम की व्याख्या के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए सूचना देने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह प्राप्त किया गया होगा जिस दिन यह नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या प्रेषित किया गया था। निर्यातक देश का उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुई है या प्राप्त जानकारी अपूर्ण है, तो प्राधिकरण एंटी-डंपिंग नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है।
26. सभी इच्छुक पक्षों को तात्कालिक मामले में अपनी रुचि (ब्याज की प्रकृति सहित) अंतरंग करने की सलाह दी जाती है और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं को दर्ज करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर सहित कोई अनुरोध करने वाले पक्षकारों (जिसमें उससे संबंधित परिशिष्ट/अनुबंध शामिल हो) से यह अपेक्षित है कि वे उस स्थिति में दो अलग-अलग क्षेत्रों में उसे प्रस्तुत करें जब उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया हो।
- (i) एक सैट पर गोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित) तथा
- (ii) दूसरे सैट पर अगोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित)।
28. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अंकित किए गए बिना प्राप्त किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस प्रकार के अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की सॉफ्ट कॉपी भी प्रत्येक के 4 (चार) सैट में हार्ड कॉपी सहित प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।
29. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना निहित होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा अन्य सूचना जो इस प्रकार की सूचना देने वाले के द्वारा गोपनीय के रूप में दावा की गई हो। सूचना के लिए जिसके संबंध में दावा गोपनीय के रूप में किया जाता है, अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया हो, सूचना देने वाले से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ इसके संबंध में भी सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।
30. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति हो और अधिमानतः इसे अनुक्रमित किया गया हो अथवा कवर किया गया हो (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उसका सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है लेकिन यह उस सूचना पर निर्भर करेगा जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश विस्तृत ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।
31. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाले इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
32. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किया गया कोई अनुरोध अथवा गोपनीयता के संबंध में सही कारण का उल्लेख किए बिना किये गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
33. संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।
- ### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
34. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाले सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

35. यदि जहां कोई हितवद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2019

Case No. SSR 14/2019

Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of Woven Fabric (having more than 50% Flax content)" commonly known as "Flax Fabric" from China PR & Hong Kong.

F.No. 7/26/2019-DGTR.—Whereas M/s Grasim Industries Limited-Jaya Shree Textiles (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the " Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), for Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of "Woven Fabric (having more than 50% Flax content)" commonly known as "Flax Fabric" (hereinafter referred as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from China PR & Hong Kong (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from China PR and Hong Kong was initiated by the Authority vide Notification No. 14/8/2008- DGAD dated 3rd October 2008. The preliminary finding was issued by the Authority on 17/02/2009, recommending provisional antidumping duty on the imports of Flax Fabrics originating or exported from China PR & Hong Kong. The provisional duties were imposed vide Customs Notification No. 30/2009-Customs dated 26th March, 2009. The Authority notified final findings vide Notification No. 14/08/2008-DGAD dated 1st October, 2009 recommending definitive antidumping duty on imports of Flax Fabrics from the subject countries. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 142/2009- Customs dated 21st December, 2009.
4. The Authority initiated 1st sunset review investigation vide Notification No.15/30/2013-DGAD dated 10th March, 2014 and conducted the investigation. The Authority thereafter extended the definitive anti-dumping duties vide Notification No.15/30/2013-DGAD dated 9th June 2015 on imports of Flax Fabric from China PR and Hong Kong. The same was imposed vide Notification No. 39/2015-Customs/ dated 12th August, 2015.

Like Article

5. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence

should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry

6. The Application has been filed by M/s Grasim Industries Limited - Jaya Shree Textiles. The Applicant has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India.
7. The application is supported by M/s Raymond and M/s Bombay Rayon. Further, following 18 small producers have also filed support letters:
 - i. M/s B K Textiles-
 - ii. M/s Baleshwar Synfab LLP
 - iii. M/s Keshari Industries Ltd.
 - iv. M/s Silverline Fashion Fabrics Ltd.
 - v. M/s Viraat fashion Weaving trends
 - vi. M/s Vrijesh Natural Fiber & Fabric (India) Pvt. Ltd.
 - vii. M/s Bhavna Fabrics
 - viii. M/s RSL Dyecot Pvt. Ltd.
 - ix. M/s Kottex Industries Pvt. Ltd.
 - x. M/s Jagdamba Textiles Pvt. Ltd.
 - xi. M/s Swasti Vinayaka Synthetics Ltd
 - xii. M/s Raghav Enterprises
 - xiii. M/s C & R Textiles Pvt. Ltd.
 - xiv. M/s Waves Madhusudhan
 - xv. M/s Minesh R Parekh
 - xvi. M/s Dharshan Creation Pvt Ltd
 - xvii. M/s Lee Weaving
 - xviii. M/s Varni Wellweave.
8. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis of likelihood of continuation or recurrence of dumping

9. Applicants have claimed that normal value in case of China should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I to the Rules. The Applicant has claimed that France should be considered as a surrogate country and has determined normal value on the basis of export price from France to other countries forming part of European Union, after due adjustments.
10. In case of Hong Kong, the Applicant has claimed normal value on the basis of consumption price in Hong Kong, determined considering import price of product into Hong Kong, after due adjustments.
11. However, the Authority for the purposes of initiation has determined normal value for the subject countries on the basis of cost of production, duly adjusted, and after additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.
12. The Applicant has claimed export prices on the basis of DGCI&S transaction wise import data. Price adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight expenses, port expenses, bank charges and marine insurance and VAT difference in case of China.
13. Considering the estimates of normal value and export price, dumping margin has been determined for each of the subject countries. The resultant dumping margin are significant and much above de-minimis limits. There is prima facie evidence that constructed normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being exported at dumped prices, thus indicating continued likelihood of dumping so as to justify initiation of investigation.

Likelihood of continuation or recurrence of Injury and Casual Link

14. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of volume effect i.e. decline in production, sales and capacity utilization and price effect due to price under cutting and price under selling leading to reduced profits, Return on Capital Employed (ROCE) and cash flows. Further, the data provided by the petitioner on the capacity and export orientation of producers/exporters in the subject countries also prima facie indicates a likelihood of dumping and consequential injury on cessation of the AD duty.

Initiation of Sunset Review of Anti-dumping investigation

15. And therefore, in view of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

Product under Consideration

16. The product under consideration as in the original investigation is Flax Fabric. As per the original investigation & SSR carried out by the Designated Authority the product has been defined as under:

“The product under consideration is “Flax Fabric” originating in or exported from China PR and Hong Kong is normally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act. “Flax” and “Linen” are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets etc. This product is classified under Customs Tariff Chapter 53 at subheading 53.09. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Woven fabric (having more than 50% flax contents) commonly known as “Flax Fabric” produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles and is the Product under Consideration within the meaning of the rules”.

The Authority notes that as per the grade-wise production statement, the domestic industry has produced fabric having flax content of 30-50%. This is 0.62% of the total production. As the domestic industry is not making substantial production of fabric having flax content of up to 50%, the Authority has therefore concluded the product under consideration to have flax content of more than 50%”

17. The subject goods are classifiable under Chapter 53 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings 5309. The Applicant has stated that subject goods are being imported under sub-headings 5309. However, the custom classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

Subject Countries

18. The investigation being a sunset review, the scope of the subject countries is confined to the subject countries in the original investigation i.e. against the subject goods originating in or exported from China PR & Hong Kong.

Period of investigation

19. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2018 to June 2019 (15 Months) and the injury investigation period will cover the periods April 2015 to March 2016, April 2016 to March 2017 and April 2017 to March 2018 and POI.

Procedure

20. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No.15/30/2013-DGAD dated 9th June 2015 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Flax Fabric from China PR & Hong Kong.
21. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of information

22. The known exporters in the subject country and their government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

34. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority